भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 661**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 06 दिसम्बर,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रत्न और आभूषणों का निर्यात

661. श्री जी. सेल्वमः

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत से रत्नों और आभूषणों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विगत वर्ष की तुलना में निर्यात में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रत्न और आभूषण उद्योग प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्रों में से एक होने के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत कुछ वर्षों में रत्न और आभूषण उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस उद्योग की स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त उद्योग से संबंधित तमिलनाडु के उद्योगों के व्यवसाय के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) वर्ष 2022-23 के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 38.11 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, जो पिछले वर्ष के 39.27 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 2.95% कम है।

(ग) 2022-23 के दौरान कुल व्यापारिक निर्यात में जी एंड जे के निर्यात का हिस्सा 8.45% है और यह उद्योग लगभग 5 मिलियन कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल को रोजगार देता है।

(घ) और (ङ) अमरीका, हांगकांग, मध्य पूर्व और चीन जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्यों में कम मांग और प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता उद्योग के समक्ष कुछ चुनौतियां थीं। सरकार ने जी एंड जे के निर्यातों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सोने और चांदी की शुल्क वापसी दरों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, एलजीडी के उत्पादन में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, 5 वर्षों की अवधि में 242.96 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईआईटी मद्रास को एक शोध परियोजना प्रदान की गई है।

(च) निर्यात संवर्धन परिषदों को बाजार पहुंच पहल (एमएआई) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र के निर्यातक सदस्य रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) में पंजीकृत हैं। तमिलनाडु के 351 निर्यात सदस्य हैं जो जीजेईपीसी के साथ पंजीकृत हैं, जो विभिन्न निर्यात संवर्धन शोज में भाग लेते हैं। वर्ष 2021 के दौरान 3.64 करोड़ रुपये की लागत से कोयंबटूर में एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किया गया था। वर्ष 2023 के दौरान त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में निर्यात संवर्धन संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

****